



Lakshya IAS

academy

15
OCT
2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)



1. पीएम गतिशक्ति के पाँच वर्ष पूरे

- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने 13 अक्टूबर 2026 को अपने पाँच वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2021 में शुरू की गई यह योजना मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बुनियादी ढाँचे से संबंधित डेटा को जीआईएस आधारित मंच पर एकीकृत करती है ताकि समन्वय और बहु-मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार किया जा सके। इसके साथ बुनियादी ढाँचा इंजनों में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और रसद बुनियादी ढाँचा शामिल हैं। यह पहल तीन संस्थागत निकायों के माध्यम से संचालित होती है: अधिकार प्राप्त सचिवों का समूह, नेटवर्क नियोजन समूह और तकनीकी सहायता इकाई। एकीकृत रसद इंटरफ़ेस मंच के माध्यम से डिजिटल एकीकरण और गति शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण कुशल बुनियादी ढाँचा नियोजन और रसद विकास को और अधिक मजबूती प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु:

- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने 13 अक्टूबर 2026 को पाँच वर्ष पूरे किए। वर्ष 2021 में शुरू की गई यह योजना 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बुनियादी ढाँचे से संबंधित भू-स्थानिक डेटा को एक साझा जीआईएस आधारित मंच पर एकीकृत करती है।
- यह योजना सात बुनियादी ढाँचा इंजनों पर ध्यान केंद्रित करती है: सड़क, रेलवे, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और रसद बुनियादी ढाँचा। इसका उद्देश्य बहु-मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार करना, अंतिम छोर तक संपर्क को मजबूत करना और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करना है।

1. PM GatiShakti Marks Five Years

- PM GatiShakti National Master Plan completed five years on October 13, 2026. Launched in 2021, it integrates infrastructure-related data from ministries, states, and union territories on a GIS-based platform to improve coordination and multimodal connectivity. Its seven infrastructure engines include roads, railways, ports, waterways, airports, mass transport, and logistics infrastructure. The initiative operates through three institutional bodies: EGoS, NPG, and TSU. Digital integration through ULIP and training provided by Gati Shakti Vishwavidyalaya further support efficient infrastructure planning and logistics development.

Key Points:

- PM GatiShakti National Master Plan completed five years on October 13, 2026. Launched in 2021, it integrates infrastructure-related geospatial data from 58 central ministries and departments and 36 states and union territories on a common GIS-based platform.
- The plan focuses on seven infrastructure engines: roads, railways, ports, waterways, airports, mass transport and logistics infrastructure. It aims to improve multimodal connectivity, strengthen last-mile connectivity and streamline infrastructure project implementation.

- 11 अगस्त 2026 तक, नेटवर्क नियोजन समूह ने लगभग 18.66 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 396 बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया था, जिनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी। इस बीच, एकीकृत रसद इंटरफ़ेस मंच ने जुलाई 2026 तक 142 एपीआई के माध्यम से 46 सरकारी रसद प्रणालियों को एकीकृत किया।

2. एनपीसीआई ने चुनिंदा यूपीआई लेन-देन पर 0.4% एमडीआर को दीवाली के बाद तक टाला

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 2,000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट यूपीआई व्यापारी लेन-देन पर 0.4% मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट के कार्यान्वयन को दीवाली के बाद तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह शुल्क, जो शुरुआत में 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना तय था, उपभोक्ताओं के बजाय व्यापारियों द्वारा चुकाया जाएगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेन-देन पर अधिकतम 300 रुपये का एमडीआर निर्धारित होगा। यह स्थगन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का समर्थन करते हुए त्योहारी और शादी के मौसम के दौरान खुदरा विक्रेताओं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सुरक्षा के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के बाद किया गया है।



मुख्य बिंदु:

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने त्योहारी और शादी के मौसम तथा व्यापार हितधारकों के साथ परामर्श का हवाला देते हुए, 2,000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट व्यक्ति-से-व्यापारी यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित 0.4% मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट के कार्यान्वयन को दीवाली 2026 के बाद तक टाल दिया है।
- प्रस्तावित रूपरेखा 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेन-देन पर अधिकतम 300 रुपये के एमडीआर का प्रावधान करती है, जबकि व्यक्ति-से-व्यक्ति लेन-देन और 2,000 रुपये तक के व्यक्ति-से-व्यापारी लेन-देन इससे मुक्त रहेंगे। एमडीआर का भुगतान व्यापारियों द्वारा किया जाना है, उपभोक्ताओं द्वारा नहीं।
- इस रूपरेखा का उद्देश्य यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, भुगतान सेवा प्रदाताओं का समर्थन करना और छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त लेन-देन लागतों से बचाना है। यह स्थगन व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रस्तावित शुल्क प्रभावी होने से पहले अधिक समय देता है।

- As of August 11, 2026, the Network Planning Group (NPG) had evaluated 396 infrastructure projects worth approximately Rs. 18.66 lakh crore, of which 256 had been sanctioned. Meanwhile, the Unified Logistics Interface Platform (ULIP) integrated 46 government logistics systems through 142 APIs by July 2026.

2. NPCI Delays 0.4% MDR on Select UPI Transactions Until After Diwali

- The National Payments Corporation of India (NPCI) has postponed the implementation of a 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) on specified UPI merchant transactions exceeding Rs. 2,000 until after Diwali. The charge, initially scheduled for October 15, 2026, will be paid by merchants rather than consumers. Transactions worth Rs. 75,000 or more will have an MDR cap of Rs. 300. The delay follows consultations with trade representatives to protect retailers and MSMEs during the festive and wedding seasons while supporting the sustainability of India's digital payment ecosystem.



Key Points:

- The National Payments Corporation of India (NPCI) has postponed the implementation of a proposed 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) on specified person-to-merchant (P2M) UPI transactions exceeding Rs. 2,000 until after Diwali 2026, citing the festive and wedding season and consultations with trade stakeholders.
- The proposed framework provides for an MDR cap of Rs. 300 on transactions worth Rs. 75,000 or above, while peer-to-peer (P2P) transactions and P2M transactions up to Rs. 2,000 remain exempt. The MDR is payable by merchants, not consumers.
- The framework aims to ensure the financial sustainability of the UPI ecosystem, support payment service providers and protect small merchants from additional transaction costs. The delay gives traders and MSMEs more time before the proposed charges take effect.

3. लक्षद्वीप बना भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश

लक्षद्वीप ने केंद्र प्रायोजित वयस्क शिक्षा योजना, उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 11 अक्टूबर 2026



को 100% साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया। एक प्रारंभिक सर्वेक्षण में 1,113 गैर-साक्षर वयस्कों की पहचान की गई थी, जिन्हें शिक्षण कार्यक्रमों और मूल्यांकनों के माध्यम से सीखने का समर्थन दिया गया। सभी पात्र शिक्षार्थियों ने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। परीक्षा केंद्रों पर आने में असमर्थ शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों ने घर-घर जाकर भी मूल्यांकन किया। यह उपलब्धि वयस्क शिक्षा, बुनियादी कौशल और सुलभ शिक्षण अवसरों के महत्व को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु:

- लक्षद्वीप को उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 11 अक्टूबर 2026 को एक पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इस पहल के तहत प्रारंभिक सर्वेक्षण के माध्यम से 1,113 वयस्क गैर-साक्षरों की पहचान की गई थी।
- सभी पात्र शिक्षार्थियों ने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर आने में असमर्थ या संकोच करने वाले शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों और पर्यवेक्षकों ने घर-घर जाकर भी मूल्यांकन किया।
- उल्लास का पूर्ण अर्थ समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ है। यह एक केंद्र प्रायोजित वयस्क शिक्षा कार्यक्रम है जो बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल और निरंतर शिक्षा को बढ़ावा देता है।

Lakshadweep Becomes India's First Fully Literate UT

Lakshadweep achieved 100% literacy status on October 11, 2026, under the ULLAS-Nav Bharat



Saaksharta Karyakram, a centrally sponsored adult education scheme. An initial survey identified 1,113 non-literate adults, who received learning support through teaching programmes and assessments. All eligible learners successfully passed the Foundational Literacy and Numeracy Assessment Test (FLNAT). Teachers also conducted doorstep assessments for learners unable to visit examination centres. The achievement highlights the importance of adult education, foundational skills and accessible learning opportunities.

Key Points:

- Lakshadweep was declared a fully literate Union Territory on October 11, 2026, under the ULLAS-Nav Bharat Saaksharta Karyakram. The initiative identified 1,113 adult non-literates through an initial survey.
- All eligible learners passed the Foundational Literacy and Numeracy Assessment Test (FLNAT), with teachers and supervisors also conducting doorstep assessments for learners unable or hesitant to visit examination centres.
- ULLAS stands for Understanding of Lifelong Learning for All in Society. It is a centrally sponsored adult education programme that promotes basic literacy, numeracy, critical life skills, vocational skills and continuing education.

4. शेफाली वर्मा ने जीता आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार

भारतीय ऑलराउंडर शेफाली वर्मा ने महिला एशिया कप और जापान में आयोजित एशियाई खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद सितंबर 2026



के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। उन्होंने सात टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 72 के औसत और 184.61 के स्ट्राइक रेट से 360 रन बनाए, साथ ही छह विकेट भी हासिल किए। वह महिला एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं और उन्होंने एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की। नवंबर 2025 में मिली जीत के बाद यह उनका दूसरा आईसीसी मासिक पुरस्कार है।

मुख्य बिंदु:

- आईसीसी ने महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय ऑलराउंडर शेफाली वर्मा को सितंबर 2026 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया। उन्होंने सात टी-20 मैचों में 72 के औसत और 184.61 के स्ट्राइक रेट से 360 रन बनाए और छह विकेट हासिल किए।
- महिला एशिया कप के दौरान, शेफाली ने पाँच पारियों में 236 रन बनाए, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में 64 रन और श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 68 रन शामिल थे। भारत ने अपना आठवां महिला एशिया कप खिताब जीता।
- नागोया, जापान में आयोजित 2026 के एशियाई खेलों में, शेफाली ने तीन पारियों में 188 रन बनाए, जिसमें सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 49 गेंदों पर बना शतक शामिल था, और चार विकेट लिए। नवंबर 2025 की अपनी पिछली जीत के बाद यह उनका दूसरा आईसीसी मासिक पुरस्कार था।

4. Shafali Verma Wins ICC Women's Player of the Month Award

Indian all-rounder Shafali Verma won the ICC Women's Player of the Month award for



September 2026 following her outstanding performances in the Women's Asia Cup and Asian Games in Japan. She scored 360 runs in seven T20I matches at an average of 72 and a strike rate of 184.61, while also taking six wickets. She was the leading run-scorer in the Women's Asia Cup and helped India secure gold at the Asian Games. This marks her second ICC monthly award, following her November 2025 win.

Key Points:

- The ICC named Indian all-rounder Shafali Verma the Women's Player of the Month for September 2026 for her performances in the Women's Asia Cup and Asian Games. She scored 360 runs in seven T20Is at an average of 72 and a strike rate of 184.61, while taking six wickets.
- During the Women's Asia Cup, Shafali scored 236 runs in five innings, including 64 in the semi-final against Bangladesh and 68 in the final against Sri Lanka. India won its eighth Women's Asia Cup title.
- At the 2026 Asian Games in Nagoya, Japan, Shafali scored 188 runs in three innings, including a century off 49 balls against Bangladesh in the semi-final, and took four wickets. This was her second ICC monthly award, following her earlier win in November 2025.

5. शुभमन गिल ने रिकॉर्ड पाँचवीं बार जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम



पर पाँचवीं बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीत लिया है। उन्होंने शुरुआती मैच में 110 रन बनाए और उसके बाद के मैच में 133 गेंदों पर 223 रन की तूफानी पारी खेली। इस उपलब्धि के साथ गिल ने वेस्टइंडीज महिला टीम की कप्तान हेली मैथ्यूज की बराबरी कर ली है, जिन्होंने पाँच बार यह पुरस्कार जीता है। भारत ने एक ही पुरस्कार चक्र में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में मासिक पुरस्कार जीतने के कई रिकॉर्ड भी दर्ज किए हैं।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपना पाँचवां आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतकर पुरुष वर्ग में अपना रिकॉर्ड आगे बढ़ाया। इस पुरस्कार ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला में उनके प्रदर्शन को मान्यता दी, जिसमें 110 रनों का एक शतक और 133 गेंदों में 223 रनों का दोहरा शतक शामिल था।
- इस उपलब्धि के साथ, गिल ने वेस्टइंडीज महिला टीम की कप्तान हेली मैथ्यूज की बराबरी कर ली, जिन्होंने पाँच बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है।
- भारत ने एक ही पुरस्कार चक्र में कई मौकों पर पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में विजेता दर्ज किए हैं। पिछले भारतीय विजेताओं में जून 2024 में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, तथा सितंबर 2025 में अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना शामिल हैं।

5. Shubman Gill Wins Record Fifth ICC Player of the Month Award

Indian captain Shubman Gill has won his fifth ICC Player of the Month award following his outstanding



performance in the ODI series against the West Indies. He scored 110 runs in the opening match and smashed 223 runs off 133 balls in the subsequent game. With this achievement, Gill has equalled West Indies women's captain Hayley Matthews, who has also won the award five times. India has also recorded multiple instances of winning both the men's and women's monthly awards in the same cycle.

Key Points:

- Indian skipper Shubman Gill won his fifth ICC Player of the Month award, extending his record in the men's category. The award recognised his performances in the ODI series against the West Indies, including a century of 110 runs and a double century of 223 runs off 133 balls.
- With this achievement, Gill equalled West Indies women's captain Hayley Matthews, who has also won the ICC Player of the Month award five times.
- India has had both the men's and women's category winners in the same award cycle on multiple occasions. Previous Indian winners include Jasprit Bumrah and Smriti Mandhana in June 2024, and Abhishek Sharma and Smriti Mandhana in September 2025.

6. अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2026

✍ आपदा रोकथाम को बढ़ावा देने और सामुदायिक मजबूती को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण



दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 का विषय, रलचिलेपन की शुरुआत घर से होती है, सुरक्षित आवास, प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, लचीले निर्माण और सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1989 में स्थापित यह दिवस आपदा से संबंधित नुकसान को कम करने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई रूपरेखा (2015-2030) चार प्राथमिकताओं के माध्यम से इन प्रयासों का मार्गदर्शन करती है, जिसमें जोखिम मूल्यांकन, शासन, लचीलेपन में निवेश, और बेहतर तैयारी तथा पुनर्प्राप्ति शामिल हैं।

मुख्य बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2026 का विषय रलचिलेपन की शुरुआत घर से होती है, जो सुरक्षित, किफायती और आपदा-प्रतिरोधी आवास, प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, उन्नत निर्माण पद्धतियों और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है।
- इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1989 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। वर्ष 2015 में, सेंडाई, जापान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में राष्ट्रों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई रूपरेखा (2015-2030) को अपनाया।
- सेंडाई रूपरेखा चार प्राथमिकताओं की पहचान करती है: आपदा जोखिमों को समझना; आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना; लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना; और पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के दौरान बेहतर पुनर्निर्माण के लिए आपदा तैयारी को बढ़ाना।

6. International Day for Disaster Risk Reduction 2026

✍ The International Day for Disaster Risk Reduction is observed annually on October 13 to promote disaster prevention and



strengthen community resilience. The 2026 theme, “Resilience Starts at Home,” highlights the importance of safe housing, effective early warning systems, resilient construction, and community participation. Established by the United Nations in 1989, the observance supports global efforts to reduce disaster-related losses. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030) guides these efforts through four priorities, including risk assessment, governance, investment in resilience, and improved preparedness and recovery.

Key Points:

- The International Day for Disaster Risk Reduction (IDDRR) is observed annually on October 13. The 2026 theme is “Resilience Starts at Home,” highlighting safe, affordable and disaster-resilient housing, effective early warning systems, improved construction practices and community participation.
- The day was established by the United Nations General Assembly in 1989 to promote global awareness and action on disaster risk reduction. In 2015, nations adopted the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015–2030) at the Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai, Japan.
- The Sendai Framework identifies four priorities: understanding disaster risks; strengthening disaster risk governance; investing in disaster risk reduction for resilience; and enhancing disaster preparedness to “Build Back Better” during recovery, rehabilitation and reconstruction.

7. विश्व बैंक ने विकासशील देशों के लिए 112 अरब अमेरिकी डॉलर की निजी पूंजी जुटाई

अध्यक्ष अजय बंगा के अनुसार, विश्व बैंक मध्य पूर्व संघर्ष के कारण ऊर्जा की बढ़ती लागत का सामना कर रहे 30 से 40 देशों के साथ वित्तीय सहायता पर चर्चा कर रहा है। इसने संकट निधि के रूप में 25 अरब अमेरिकी डॉलर निर्धारित किए हैं, जबकि अनुमोदित परियोजनाओं के पुनर्वितरण के माध्यम से अन्य 35 अरब अमेरिकी डॉलर संभावित रूप से उपलब्ध हो सकते हैं। यदि स्थिति और बिगड़ती है तो यह सहायता 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है। बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 112 अरब अमेरिकी डॉलर का निजी वित्त भी जुटाया है। ऋण-के-बदले-विकास अदला-बदली और वित्तीय गारंटी उन उपायों में शामिल हैं जो ऋण दबाव को कम करने और विकासशील देशों में आवश्यक विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए अपनाए जा रहे हैं।



मुख्य बिंदु:

- अध्यक्ष अजय बंगा के नेतृत्व में विश्व बैंक मध्य पूर्व संघर्ष के बीच ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से प्रभावित 30 से 40 देशों के साथ संभावित सहायता पर चर्चा कर रहा है। इसने संकट निधि में 25 अरब डॉलर अलग रखे हैं, जिसमें स्वीकृत परियोजनाओं से पुनर्वितरण के माध्यम से अन्य 35 अरब अमेरिकी डॉलर संभावित रूप से उपलब्ध हो सकते हैं। हालात बिगड़ने पर कुल सहायता 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है।
- विकासशील देश बढ़ते ऋण भार और उच्च उधारी लागत के साथ-साथ ऊर्जा, परिवहन, बिजली और उर्वरकों की बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि लेनदारों को विकासशील देशों का बाह्य ऋण भुगतान 2026 में लगभग 400 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, जिसमें से लगभग एक-तिहाई हिस्सा केवल ब्याज भुगतान का होगा।
- विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 112 अरब अमेरिकी डॉलर का निजी वित्त जुटाया, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 69 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह उधार लेने की लागत को कम करने और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जल तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों के लिए संसाधन मुक्त करने के लिए ऋण-के-बदले-विकास अदला-बदली और वित्तीय गारंटी का भी उपयोग कर रहा है।

7. World Bank Mobilises USD 112 Billion in Private Capital for Developing Countries

The World Bank is discussing financial assistance with 30-40 countries facing rising energy costs due to the Middle East conflict, according to President Ajay Banga. It has earmarked USD 25 billion in crisis funding, with another USD 35 billion potentially available through reallocations. Assistance could reach USD 100 billion if conditions worsen. The Bank also mobilised a record USD 112 billion in private finance in FY2026. Debt-for-development swaps and financial guarantees are among its measures to ease debt pressures and support essential development programmes in developing countries.



Key Points:

- The World Bank, led by President Ajay Banga, is discussing possible assistance with 30-40 countries affected by rising energy prices amid the Middle East conflict. It has set aside USD 25 billion in crisis funding, with another USD 35 billion potentially available through reallocations from approved projects. Total assistance could reach USD 100 billion if conditions worsen.
- Developing countries face rising costs of energy, transport, electricity and fertilisers, alongside mounting debt burdens and higher borrowing costs. The World Bank estimated that developing countries' external debt payments to creditors would reach around USD 400 billion in 2026, with approximately one-third comprising interest payments.
- The World Bank mobilised a record USD 112 billion in private finance in FY2026, compared with USD 69 billion in FY2025. It is also using debt-for-development swaps and financial guarantees to reduce borrowing costs and free up resources for sectors such as education, healthcare, water and environmental protection.

8. आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7% किया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मजबूत घरेलू मांग और सशक्त सेवा गतिविधियों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 60 आधार अंक बढ़ाकर 6.4% से



7% कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक और ओईसीडी ने विकास दर 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। भारत की आर्थिक संभावनाओं को अनुकूल जनसांख्यिकी, संरचनात्मक सुधारों और व्यापार समझौतों से समर्थन प्राप्त है। हालाँकि, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें और भू-राजनीतिक तनाव जोखिम पैदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक विकास दर 2026 में 3.1% और 2027 में 3.4% रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें वैश्विक मुद्रास्फीति के धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मजबूत घरेलू मांग, मजबूत सेवा क्षेत्र गतिविधि और सकारात्मक आर्थिक गति का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.4% से 60 आधार अंक बढ़ाकर 7% कर दिया है। दी गई रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक और ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 7.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुकूल जनसांख्यिकी, बढ़ते घरेलू बाजार और संरचनात्मक सुधारों को भारत के आर्थिक विकास के प्रमुख चालकों के रूप में रेखांकित किया। यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौतों से व्यापार को समर्थन मिलने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की उम्मीद है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2026 में 3.1% और 2027 में 3.4% रहने का अनुमान लगाया है, जिसके तहत 2027 में 4.1% तक गिरने से पहले 2026 में वैश्विक मुद्रास्फीति 4.7% तक पहुँचने की उम्मीद है। भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतें और असमान विकास की संभावनाएँ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख जोखिम बनी हुई हैं।

8. IMF Raises India's FY27 GDP Growth Forecast to 7%

The International Monetary Fund (IMF) has raised India's FY27 GDP growth forecast by 60 basis points, from 6.4% to 7%, citing strong domestic demand and robust services activity. The RBI, World Bank and OECD have projected growth at 7.1%. India's economic prospects are supported by favourable demographics, structural reforms and trade agreements. However, rising energy prices and geopolitical tensions pose risks. The IMF projects global growth at 3.1% in 2026 and 3.4% in 2027, with global inflation expected to moderate gradually.



Key Points:

- The International Monetary Fund (IMF) raised India's GDP growth projection for FY 2026-27 to 7%, an increase of 60 basis points from 6.4%, citing strong domestic demand, robust services sector activity and positive economic momentum. The RBI, World Bank and OECD have projected growth of 7.1% for FY27, according to the provided report.
- The IMF highlighted favourable demographics, a growing domestic market and structural reforms as key drivers of India's economic growth. Free Trade Agreements (FTAs), including those with the UK, the European Union and New Zealand, are expected to support trade and strengthen supply chains.
- The IMF projected global GDP growth at 3.1% in 2026 and 3.4% in 2027, with global inflation expected to reach 4.7% in 2026 before declining to 4.1% in 2027. Geopolitical tensions, elevated energy prices and uneven growth prospects remain major risks to the global economy.

9. सितंबर 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 5.54% पर पहुँची

✂ भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त के 4.83% से बढ़कर सितंबर 2026 में 5.54% हो गई, जो अक्टूबर 2024 के बाद का इसका उच्चतम स्तर है।



सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, मुख्य रूप से सब्जियों, विशेष रूप से प्याज, लहसुन और अदरक की बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 7.74% हो गई। ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति क्रमशः 6.08% और 4.88% रही। खाद्य और कच्चे तेल की कीमतों के दबाव तथा मौसम संबंधी जोखिमों का हवाला देते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को 5% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया। मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 2-6% के स्वीकार्य दायरे के भीतर बनी रही।

मुख्य बिंदु:

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त के 4.83% से बढ़कर सितंबर 2026 में 5.54% हो गई, जो अक्टूबर 2024 के बाद से इसका उच्चतम स्तर है। खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 7.74% हो गई, जो सब्जियों, विशेष रूप से प्याज, लहसुन और अदरक की बढ़ती कीमतों से प्रेरित थी। संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला 2024 को अपने आधार वर्ष के रूप में उपयोग करती है।
- ग्रामीण मुद्रास्फीति बढ़कर 6.08% हो गई, जबकि शहरी मुद्रास्फीति 4.88% तक पहुँच गई। अन्य योगदान देने वाले कारकों में कच्चे तेल की उच्च कीमतें, प्रतिकूल मौसम के जोखिम और कमजोर रुपया शामिल थे, जिससे आयात लागत में वृद्धि हुई। रेस्तरां और होटलों में मुद्रास्फीति 9.36% रही, जबकि माल दुलाई सेवाओं में 14.73% दर्ज की गई।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों तथा मौसम संबंधी जोखिमों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.0% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया। भारत के लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचे के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक का लक्ष्य मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखना है, जिसकी स्वीकार्य सीमा 2-6% है।

9. India's Retail Inflation Hits 5.54% in September 2026

✂ India's retail inflation rose to 5.54% in September 2026 from 4.83% in August, reaching its highest level since October



2024. According to MoSPI, food inflation increased to 7.74%, driven mainly by rising vegetable prices, particularly onions, garlic and ginger. Rural and urban inflation stood at 6.08% and 4.88%, respectively. Citing food and crude oil price pressures and weather-related risks, the RBI raised its FY27 inflation forecast from 5% to 5.2%. Inflation remained within the RBI's permissible range of 2-6%.

Key Points:

- India's retail inflation, measured by the Consumer Price Index (CPI), rose to 5.54% in September 2026 from 4.83% in August, reaching its highest level since October 2024. Food inflation increased to 7.74%, driven by rising prices of vegetables, particularly onions, garlic and ginger. The revised CPI series uses 2024 as its base year.
- Rural inflation rose to 6.08%, while urban inflation reached 4.88%. Other contributing factors included higher crude oil prices, adverse weather risks and a weaker rupee, which increased import costs. Inflation in restaurants and hotels stood at 9.36%, while freight services recorded 14.73%.
- The Reserve Bank of India (RBI) raised its FY 2026-27 inflation projection from 5.0% to 5.2%, citing rising crude oil and food prices and weather-related risks. Under India's flexible inflation-targeting framework, the RBI aims to maintain inflation at 4%, with a permissible range of 2-6%.

10. राष्ट्रपति मुर्मू ने बड़े फेरबदल में छह राज्यपालों की नियुक्ति की

✎ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्टूबर 2026 को छह राज्यपालों की नियुक्तियों और तबादलों की घोषणा की, जिसमें ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। ब्रज मोहन राम, डॉ. सुधा यादव, डॉ. ढाल सिंह बिसेन और दुष्यंत गौतम को राज्यपाल के रूप में नई नियुक्तियाँ मिलीं। ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम से केरल स्थानांतरित किया गया, जबकि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल से तमिलनाडु चले गए। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि अनुच्छेद 156 उनके कार्यकाल और पद पर बने रहने को नियंत्रित करता है।



मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्टूबर 2026 को छह राज्यों के राज्यपालों के फेरबदल की घोषणा की, जिसमें चार नई नियुक्तियाँ और दो तबादले शामिल हैं। ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल, डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक, डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड और दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
- सिक्किम के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जबकि केरल के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया। ये नियुक्तियाँ संबंधित राज्यपालों द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।
- अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है; अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति से संबंधित है; अनुच्छेद 156 उनके कार्यकाल और राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहने से संबंधित है; और अनुच्छेद 157 आवश्यक योग्यताओं को निर्दिष्ट करता है। राज्यपाल को कम से कम 35 वर्ष की आयु का भारतीय नागरिक होना चाहिए, और सामान्य कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पाँच वर्ष का होता है।

10. President Murmu Appoints Six Governors in Major Reshuffle

✎ President Droupadi Murmu announced six gubernatorial appointments and transfers on October 12, 2026, covering Odisha, Karnataka, Uttarakhand, Sikkim, Kerala and Tamil Nadu. Braj Mohan Ram, Dr Sudha Yadav, Dr Dhal Singh Bisen and Dushyant Gautam received new appointments as governors. Om Prakash Mathur was transferred from Sikkim to Kerala, while Rajendra Vishwanath Arlekar moved from Kerala to Tamil Nadu. Under Article 155 of the Constitution, state governors are appointed by the President, while Article 156 governs their tenure and continuation in office.



Key Points:

- President Droupadi Murmu announced a reshuffle of six state governors on October 12, 2026, comprising four new appointments and two transfers. Braj Mohan Ram was appointed Governor of Odisha, Dr Sudha Yadav of Karnataka, Dr Dhal Singh Bisen of Uttarakhand, and Dushyant Gautam of Sikkim.
- Om Prakash Mathur, the former Governor of Sikkim, was appointed Governor of Kerala, while Rajendra Vishwanath Arlekar, the former Governor of Kerala, was appointed Governor of Tamil Nadu. The appointments take effect upon the respective governors assuming office.
- Article 153 provides for state governors; Article 155 deals with their appointment by the President; Article 156 covers their tenure and the President's pleasure; and Article 157 specifies the qualifications. A Governor must be an Indian citizen aged at least 35 years, and the normal tenure is five years, subject to the President's pleasure.



दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS

MCQs

प्रश्नोत्तरी

Q1. 12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यपालों की नियुक्तियों और तबादलों की घोषणा की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है?

- (a) अनुच्छेद 153 (b) अनुच्छेद 156
(c) अनुच्छेद 152 (d) अनुच्छेद 155

Q2. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, सितंबर 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी?

- (a) 4.83% (b) 5.20%
(c) 5.54% (d) 6.08%

Q3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मजबूत घरेलू मांग और सशक्त सेवा गतिविधियों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है?

- (a) 6.6% (b) 6.8%
(c) 7.0% (d) 7.2%

Q4. रिपोर्ट के अनुसार, मध्य पूर्व संघर्ष के कारण ऊर्जा की बढ़ती लागत का सामना कर रहे देशों की सहायता के लिए विश्व बैंक ने कितनी संकट निधि निर्धारित की है?

- (a) 15 अरब अमेरिकी डॉलर
(b) 25 अरब अमेरिकी डॉलर
(c) 35 अरब अमेरिकी डॉलर
(d) 50 अरब अमेरिकी डॉलर

Q5. अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस आयोजन का आधिकारिक विषय क्या था?

- (a) आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश
(b) लचीलेपन की शुरुआत घर से होती है
(c) सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी
(d) बेहतर पुनर्निर्माण

Q1. On October 12, 2026, President Droupadi Murmu announced several gubernatorial appointments and transfers. Under which Article of the Indian Constitution are state governors appointed by the President?

- (a) Article 153
(b) Article 156
(c) Article 152
(d) Article 155

Q2. According to the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), what was India's retail inflation rate in September 2026?

- (a) 4.83%
(b) 5.20%
(c) 5.54%
(d) 6.08%

Q3. The International Monetary Fund (IMF) raised India's GDP growth forecast for FY2026-27 from 6.4% to what percentage, citing strong domestic demand and robust services activity?

- (a) 6.6%
(b) 6.8%
(c) 7.0%
(d) 7.2%

Q4. According to the report, how much crisis funding has the World Bank earmarked to assist countries facing rising energy costs due to the Middle East conflict?

- (a) USD 15 billion
(b) USD 25 billion
(c) USD 35 billion
(d) USD 50 billion

Q5. The International Day for Disaster Risk Reduction is observed annually on October 13. What was the official theme of the observance in 2026?

- (a) Investing in Disaster Risk Reduction
(b) Resilience Starts at Home
(c) Early Warning for All
(d) Building Back Better

- Q6. दी गई रिपोर्ट के अनुसार, किस भारतीय क्रिकेटर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के दम पर अपना पाँचवां आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता ?
- (a) रोहित शर्मा (b) शुभमन गिल
(c) विराट कोहली (d) श्रेयस अय्यर
- Q7. किस भारतीय क्रिकेटर ने सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता ?
- (a) स्मृति मंधाना (b) हरमनप्रीत कौर
(c) जेमिमा रोड्रिग्स (d) शेफाली वर्मा
- Q8. लक्षद्वीप ने 11 अक्टूबर 2026 को निम्नलिखित में से किस सरकारी कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया ?
- (a) समग्र शिक्षा अभियान
(b) उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
(c) राष्ट्रीय शिक्षा मिशन
(d) पीएम श्री स्कूल योजना
- Q9. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 2,000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट यूपीआई व्यापारी लेन-देन पर मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट के कार्यान्वयन को दीवाली 2026 के बाद तक के लिए टाल दिया है। इन लेन-देन के लिए प्रस्तावित एमडीआर दर क्या है ?
- (a) 0.2% (b) 0.3%
(c) 0.4% (d) 0.5%
- Q10. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने 13 अक्टूबर 2026 को पाँच वर्ष पूरे किए। निम्नलिखित में से कौन सी पहल पीएम गतिशक्ति के उद्देश्यों को पूरा करते हुए भारत में रसद संबंधी सेवाओं के लिए डिजिटल एकीकरण और सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है ?
- (a) एकीकृत रसद इंटरफ़ेस मंच
(b) प्रधानमंत्री जन धन योजना
(c) डिजिटल भारत भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
(d) अटल पेंशन योजना

- Q6. Which Indian cricketer won his fifth ICC Player of the Month award following his performance in the ODI series against the West Indies, according to the given report?
- (a) Rohit Sharma (b) Shubman Gill
(c) Virat Kohli (d) Shreyas Iyer
- Q7. Which Indian cricketer won the ICC Women's Player of the Month award for September 2026?
- (a) Smriti Mandhana
(b) Harmanpreet Kaur
(c) Jemimah Rodrigues
(d) Shafali Verma
- Q8. Lakshadweep achieved 100% literacy status on October 11, 2026, under which of the following government programmes?
- (a) Samagra Shiksha Abhiyan
(b) ULLAS-Nav Bharat Saaksharta Karyakram
(c) National Education Mission
(d) PM SHRI Schools Scheme
- Q9. The National Payments Corporation of India (NPCI) has postponed the implementation of a Merchant Discount Rate (MDR) on specified UPI merchant transactions exceeding ₹2,000 until after Diwali 2026. What is the MDR rate proposed for these transactions?
- (a) 0.2% (b) 0.3%
(c) 0.4% (d) 0.5%
- Q10. The PM GatiShakti National Master Plan completed five years on October 13, 2026. Which of the following initiatives facilitates digital integration and information exchange for logistics-related services in India, complementing the objectives of PM GatiShakti?
- (a) Unified Logistics Interface Platform (ULIP)
(b) Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)
(c) Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP)
(d) Atal Pension Yojana (APY)

उत्तरमाला (Answer Key)

1 D 2 C 3 C 4 B 5 B 6 B 7 D 8 B 9 C 10 A

